LOK SABHA

Wednesday March 23, 1983/Chaitra 2, 1905 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

श्री हरिकेश बहादर अध्यक्ष महोदय, डी०टी०सी० में आज हड़ताल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो टाइम से आ गये, आज तो थोड़ी सी ही घंटी बजी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : आज किसी तरीके से आ पाये हैं, नहीं तो आ नहीं पाते । सारी की सारी बसें बन्द हैं ।

एक माननीय सदस्य : बड़ी कठिनाई है ।

श्री राम विलास पासवान : या तो डी०टी०सी० की हड़ताल खत्म करवाइये, या हम लोगों की बसें बढ़वाइये ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, तुम्हारी बस चलवा देते हैं ।

श्री फूलचन्द वर्मा

श्री हरिकेश बहादुर: इस पर कोई बहस होगी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इनकी चुनी हुई असेम्बली बैठी है, मट्रोपोलिटन काउंसिल है ।

श्री राम विलास पासवान : जब पार्लियामेंट बैठी है तो असेम्बली इसमें क्या करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : It is their job; not yours.

आप उनके काम में अनाधिकार क्यों करते हैं ?

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के कारण हानि

+

***349. श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए 1600 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विस्तार योजना के परिणामस्वरूप हानि हुई है ;

(ग) क्या इस हानि का निर्धारण कर लिया गया था और यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या इस हानि का कारण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई मशीनें/संयंत्र थे ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE): (a) The approved cost estimate of Bhilai Steel Plant expansion project is Rs. 1600.5

crores and the project is at an advanced stage of implementation.

(b) No, Sir.

(c and (d). Do not arise.

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय मंत्री ने गोल-गोल उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : गोल-गोल ।

श्री सतीश अग्रवाल : गोल-गोल का ट्रांस्लेशन क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय: गोल-गोल का ट्रांस्लेशन है लड्डू ।

श्री फूलचन्द वर्मा : जीरो ।

AN HON. MEMBER: Round and round.

PROF. MADHU DANDAVATE: He represents the Earth.

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष म होय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सभा के 7 अक्तूबर, 1982 के क्वैश्चन न० 390 और लोक-सभा के 11 सितम्बर, 1981 के क्वैश्चन न० 3923 के जवाब में जो बात मंत्री महोदय ने कही है, वह इससे कुछ भिन्न दिखाई दे रही है ।

मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भिलाई इस्पात कारखाने में जो महा-प्रबन्धक मि० भाटिया हैं, उन्होंने इस कारखाने में जो एक्सपैंशन का काम चल रहा है, उसकी लागत में जो वृद्धि हो रही है, उसके पीछे कारण यह बताया है कि बी०एच०ई०एल० से जो 700 हार्स पावर की मोटर उन्होंने लगवाई थी, वह जल गई । इसके कारण उनका आक्सीजन प्लान्ट समय पर नहीं बन सका और इस कारण लागत में वृद्धि हो गई है ।

मैं जानना चाहता हूं कि यह प्लान्ट कब तक पूर्ण रूपेण शुरू हो जायेगा और जिस प्रकार का कारण मि० भाटिया ने बताया है, उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : मान्यवर, प्रश्न अगर आप देखें तो वह यह है कि

"Whether a Rs. 1600 crore scheme was formulated for the expansion of Bhilai Steel Plant; if so, whether it is a fact that loss has been suffered as a result of this expansion scheme;"

"(a) whether a Rs. 1600 crore scheme was formulated for the expansion of Bhilai Steel Plant;

(b) If so, whether it is a fact that loss has been suffered as a result of this expansion scheme."

इसका मैंने जवाब दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : जहां तक दूसरी बात का सवाल है, या सही है कि मेल से जो कुछ माल हमने खरीदा था, वहां पर एक्सपैंशन के लिये, उसमें कुछ डेफेक्टिव माल आया, वह माल हमने मेल को वापिस किया और मेल ने दोबारा उसको रेक्टिफाई करके हमें लगाने के लिए दिया । इसमें देरी जरूर हुई है लेकिन मुल्क के डेवलपमेंट की इस स्टेज पर इस तरह की बात का होना अनिवार्य है । मेल भी एक पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग है । हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्लान्ट पूरा हो जाए ।

आप ने यह भी पूछा है कि कब पूरा होगा । मान्यवर, मेरा जवाब है :

According to the revised commissioning schedule, all units except the 7th Blast Furnace will be commissioned in March 1984 and the 7th Blast Furnace

Complex will be completed in December, 1984.

श्री फूलचन्द वर्मा : मन्त्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि पब्लिक सेक्टर में जो काम होते हैं उसमें इस प्रकार की देरी और मूल्यवृद्धि होनी अनिवार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं कहा है । उन्होंने कहा है कि तरक्की कर रहे देश में ऐसा होता है

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारा टार्गेट था उसके मुताबिक यह कारखाना मार्च-अप्रैल, 1983 में चालू होना था लेकिन इस विलम्ब के कारण इसमें एक साल की देरी हो गई है । आपके कथनानुसार अब यह कारखाना मार्च, 1984 में चालू होगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मंहगाई और प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस 1600 करोड़ की योजना पर और कितने करोड़ लग जायेंगे—इसको माननीय मन्त्री जी स्पष्ट कर दें ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : अभी तक हमारा एस्टिमेट 1600 करोड़ का ही है । 28 फरवरी तक हमने उस पर 1151.05 करोड़ खर्च किए हैं और 1600 करोड़ में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यह सही है कि जो विलम्ब हो गया है, उसकी वजह से 1.05 मिलियन टन प्रोडक्शन का लास हो गया है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की उन्नति का यह भी मापदण्ड होता है कि देश में इस्पात की कितनी खपत हो रही है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात को बताएगी कि जो यह अनुमान है कि 2000 ई० तक देश में इस्पात आपूर्ति और खपत के बीच 13.4 मिलियन टन की कमी रहेगी, उसकी आपूर्ति के लिए कोई अल्पकालीन योजना बनाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसमें कहां पैदा होता है ?

श्री एन०के० पी० साल्वे : इस सवाल से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

SHRI S. T. QUADRI: The hon. Minister in his reply has mentioned about the expansion scheme of the Bhilai Steel Plant and the second part of the question was that because of the burning of the 700 hp motor there was a production loss. Sir, when the scheme has not been completed, the question of burning of the motor does not arise. Is it that this loss on account of the burning of the motor in the existing plants or is it that in the trial production itself, the equipment supplied by BHEL has failed?

SHRI N.K.P. SALVE: In reply to the question of the hon. member, I never confirmed that the delay was on account of the burning of the motor. I merely said that there was delay in supplies of some of the equipment ordered from BHEL. Therefore, the second part of the question of the hon. Member does not arise.

SHRI C. T. DHANDAPANI: I would like to have a clarification from the hon. Minister with regard to the production of steel. There are three major industries in the country owned by the Government. These three steel industries were not able to achieve the target. Even if you take the figures of some years, they were not able to achieve the target. Despite this fact, I do not know why the Government is investing money in the same factories for expansion purposes. When you are not able to achieve the target, what is the necessity for the Government to invest more money for expansion purposes?

SHRI N.K.P. SALVE: Firstly, as a matter of fact, we do not have 3 but we have 5 integrated steel plants in the public sector. Secondly, because we are not able to achieve the target to be able to

achieve the target we have to revamp and modernise the plants and once we have done that, it would be far cheaper to produce steel. It is one way to reckon the cost for a ton of production. It will be far cheaper if we augment the capacity of the existing plants than to put up new plants.

SHRI C. T. DHANDAPANI: Modernisation is different.

SHRI N.K.P. SALVE: Sir, in my reply I said both. My second part of the reply was that expansion or augmentation of the capacity of the existing plants is much cheaper and it is one way to reduce the cost of steel per tonne.

Practice of Carrying Night Soil as Head Load

*350. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) measures taken by Government so far to end the inhuman practice of carrying night soil as head load by the scavengers which is directly related to the practice of untouchability;

(b) special allocations, if any, made by the Government during the Fifth and Sixth Plan periods;

(c) the actual amount spent for the benefit and uplift of these people and the results achieved; and

(d) measures taken by the Government to implement the recommendations|suggestions of Commissions|Committees set up for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The long-term solution to this problem lies in the conversion of all dry latrines into sanitary ones as part of the sanitation programme under the State Sector.

However, the Ministry of Home Affairs have been providing matching assistance to the State Governments out of a limited allocation under the "Centrally Sponsored Scheme for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955". The Scheme has components namely (i) machinery for implementation of PCR Act and (ii) liberation of scavengers. Under the second component of this Centrally sponsored scheme, matching grants are given to the State Governments for conversion of dry latrines into water borne latrines in some selected towns.

(b) The total allocation for both the components of the said scheme during the VI Five Year Plan is Rs. 6 crores.

(c) The following amounts were released to the State Governments for the conversion of dry latrines into water borne latrines during 1980-81, 1981-82 and 1982-83 (upto 21-3-1983):—

Year	Amount related (Rs. in lakhs)
1980-81	63.00
1981-82	131.12
1982-83	171.35

In Bihar the eight towns, namely: Bihar-Sharif, Purnea, Chaibasa, Madhubani, Ranchi, Saharsa, Deoghar and Daltonganj have been made scavenging-free. The work in some other towns in Bihar and other States is in progress.

(d) The Government of India has not set up any Commission|Committee during the recent years.

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । हिन्दुस्तान की आज़ादी के 35 साल के बाद भी 2,968 स्माल टाउन्स के अन्दर 8 लाख सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें 3 लाख 20 हज़ार लोग गांधी जी के देश में मला उठाते हैं । इस से लज्जा की ओर क्या बात हो सकती है ? माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बिहार के आठ-नौ कस्बों का ज़िक्र किया है ।